हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

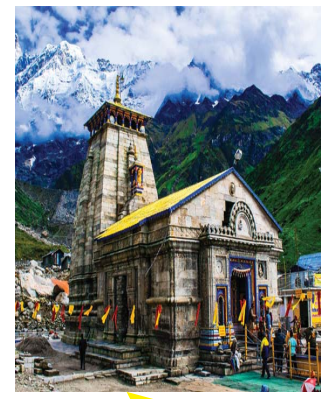

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:5 अंक:01 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, रविवार, 04 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखण्ड की सड़क कनेक्टिविटी को प्रदान करेंगे नई मजबूती

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखण्ड में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीघ्र ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करेंगे। इस प्रस्तावित मुलाकात में राज्य की कई महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर ठोस पैरवी की जाएगी। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ, जिसमें प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति, प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग तथा अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग से जुड़े प्रस्ताव प्रमुखता से रखे जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा

कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से उत्तराखण्ड का सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा, यातायात व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में ऐतिहासिक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से चारधाम यात्रा, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास को बल मिलेगा। ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में हाथी कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड मार्ग, चंद्रभागा नदी पर सेतु और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है, जिससे ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात निर्बाध हो सकेगा। अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309बी के अंतर्गत 76 किलोमीटर लंबाई में दो लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 988 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109 के तहत 235 किलोमीटर लंबाई में दो लेन चौड़ा करने का सरेखण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309ए के अंतर्गत विभिन्न पैकेजों में 84.04 किलोमीटर लंबाई में 1001.99 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रस्तावित हैं। काण्डा से बागेश्वर खंड के लिए वनभूमि हस्तांतरण की स्वीकृति भी भारत सरकार से मिल चुकी है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रस्तावित परियोजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल पर उत्तराखंड के माल्टा को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में माल्टा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 'माल्टा मिशन' शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के माल्टा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी गीता पुष्कर धामी के साथ विभिन्न जनपदों से आए माल्टा, नींबू एवं अन्य साइट्रस फलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने माल्टा एवं नींबू की खटाई सहित इन फलों से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी लिया और किसानों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान और परंपरा से जुड़ा हुआ फल है। राज्य की आर्थिकी को सशक्त बनाने में बागवानी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार पहले ही एप्पल मिशन और कीवी मिशन जैसी योजनाएं

शुरू कर चुकी है और अब माल्टा मिशन के माध्यम से किसानों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग, बेहतर विपणन और बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रत्येक जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में आयोजित होने वाला माल्टा महोत्सव राज्य के किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि खेती और बागवानी में नवाचार, आधुनिक तकनीक और उचित प्रोत्साहन से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी यह पहल गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि राज्य में माल्टा, सेब, नाशपाती, कीवी, अखरोट, आड़ू और नींबू वर्गीय फलों के बागान विकसित किए जा रहे हैं। फसल आधारित क्लस्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माल्टा और गलगल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। बागान स्थापना पर 50 प्रतिशत, सूक्ष्म सिंचाई पर 70 से 80 प्रतिशत तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

महोत्सव में पौड़ी गढ़वाल के माल्टा उत्पादक हरीश के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 53 प्रजातियों के लगभग एक हजार पौधे रोपित किए हैं, जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, कैलाश पंत, प्रताप सिंह पंवार, सचिव कृषि एस.एन. पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न जनपदों से आए किसान उपस्थित रहे।

वेनेजुएला में धमाकों के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, मादुरो और पत्नी की गिरफ्तारी का ऐलान

नई दिल्ली । वेनेजुएला की राजधानी करकस में शनिवार देर रात एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।

हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ट्रंप की घोषणा से कुछ घंटे पहले करकस और उसके आसपास तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई इलाकों में आग, धुआं और जलती इमारतें दिखाई दीं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। करकस में कम से कम सात धमाके हुए और फाइटर जेट्स की उड़ान भी देखी गई। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जबकि लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी मीडिया संस्थानों अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि इन हमलों में अमेरिकी सेना की भूमिका थी।

वहीं, वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति मादुरो की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की संप्रभुता और जनता के खिलाफ किया गया यह सैन्य आक्रमण बेहद गंभीर है और इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने खारिज किया जाता है।

गौरतलब है कि ट्रंप बीते कई हफ्तों से वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी हमले की धमकी दे रहे थे।

एक नजर

गगौवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस ने दो गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा बताया गया कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बुग्गी में 2 गौवंशीय पशुओं को रस्सी से बाँधकर क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए दो व्यक्तियों को मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों गौवंशीय पशुओं को मुक्त कर सकुशल सुरक्षित गौशाला भिजवाया गया। आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली लक्सर पर मु0अ0सं0 20/2026 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। आरोपियों के नाम मोमीन पुत्र शरीफ, निवासी ग्राम मुंडलाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार और अनिकेत पुत्र विंदरपाल, निवासी ग्राम मुंडलाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार बताए गए हैं।

शिवा उर्फ लड्डू गैंग का लीडर साथी समेत गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर की जा रही कार्रवाई के तहत श्यामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्यामपुर पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों (स्मैक, चरस, गांजा आदि) की तस्करी में लिप्त शिवा उर्फ लड्डू गैंग के कुल 3 सदस्यों के विरुद्ध थाना श्यामपुर पर दिनांक 01.01.2026 को मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगणों एवं थानाध्यक्ष श्यामपुर के निर्देशन में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गईं। पुलिस टीम ने 2 जनवरी को उत्कृष्ट सुरागरसी-पतारसी के आधार पर अभियुक्त शिवा उर्फ लड्डू पुत्र महेन्द्र, निवासी ग्राम कांगड़ी, थाना श्यामपुर, जनपद हरिद्वार (गैंग लीडर) को उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया गया। दूसरी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मदन शर्मा पुत्र सुखवीर, निवासी हरिपुरकलां, थाना रायवाला, जनपद देहरादून को उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही गैंग के अन्य फरार सदस्य की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है तथा सर्विलांस टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है।

दिल्ली की विवाहिता को ताबीज बनवाने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म

प?थ प्रवाह, हरिद्वार। दिल्ली की एक विवाहिता को ताबीज बनवाने के बहाने धर्मनगरी बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला ज्वालापुर कोतवाली स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। इसी दौरान किसी परिचित ने उस पर साया होने की बात कहकर उसे मानसिक रूप से डरा दिया। इसी बीच सुभाषनगर दिल्ली निवासी सोनू सिंह का उसके घर आना-जाना था। आरोपी ने विश्वास में लेकर कहा कि हरिद्वार में ताबीज बनवाने से उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। 28 नवंबर को वह महिला को हरिद्वार ले आया। बताया गया कि यात्रा के दौरान पीड़िता की बुआ की बेटी और एक अन्य युवक भी साथ था। हरिद्वार पहुंचने पर आरोपी ने ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित अपनी बहन के घर ठहराया। आरोप है कि वहां शराब मंगवाकर पीड़िता को पिला दी गई। नशे की हालत में आरोपी ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।अगले दिन पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया और पति को छोड़ने का दबाव बनाया। इसके बाद वह महिला को मनसा देवी पहाड़ी क्षेत्र में ताबीज दिलवाने के बहाने ले गया और फिर दिल्ली लौट आया। आरोप है कि इसके बाद से आरोपी लगातार महिला को धमका रहा है और पति की हत्या की धमकी देकर दबाव बना रहा है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि दिल्ली से प्राप्त जीरो एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लगाएं विशेष कैम्प: जिलाधिकारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिला प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी दिव्यांगजनों को शत प्रतिशत प्रमाण देने और उनके यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिये। जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र का संचालन खिदमत वेलफेयर सोसायटी लक्सर के द्वारा राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की में किया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों एवं यूडीआईडी की समीक्षा के दौरान प्रबंधक, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसम्बर तक 1190 प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए सहयोग प्रदान किया गया। संस्था की टीम के द्वारा 1349 यूडीआईडी कार्डों को बनाया गया। जनपद में दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण की समीक्षा करने पर प्रबंधक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,450 सर्वे का कार्य किया जा चुका है। निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हरिद्वार को कार्मिकों के मानदेय व्यय के लिए आवंटित की गयी धनराशि को डीडीआरसी को भुगतान के लिए समिति द्वारा सहमति दी गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जाए। सभी दिव्यांजनों के यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य रूप से निर्गत किए जाए। उन्होंने दिव्यांगों के लिए सर्वेक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के निर्देश दिए। जनपद में स्वरोजगार इच्छुक दिव्यागजनों की सूची उपलब्ध कराने निर्देश भी दिए ताकि उन्हें विभिन्न कंपनियों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। बैठक में सीएमओ डॉ आरके सिंह, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिजीत सिंह, प्रतिनिधि जिला प्रोबेशन अधिकारी हेम तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

उर्मिला और सुरेश राठौर के ऑडियो-वीडियो के जरिए हो रहा दुष्प्रचार : संदीप खत्री

पथ प्रवाह, हरिद्वार

रविदासीय धर्म प्रचारक संदीप खत्री ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऑडियो-वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाने वालों से पुलिस के समक्ष ठोस सबूत प्रस्तुत करने की मांग की है। शनिवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संदीप खत्री ने कहा कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो-वीडियो प्रसारित कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि इनके पास कोई भी प्रमाण या ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर फैलाने के बजाय सीधे जांच एजेंसियों और पुलिस प्रशासन को सौंपना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि केवल बातचीत के आधार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों ही अपने दावों को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। संदीप खत्री ने कहा कि यह भी गंभीर प्रश्न है कि दोनों आरोप लगाने वाले पुलिस प्रशासन से क्यों बचते फिर रहे हैं। यदि वे स्वयं को सच्चा मानते हैं, तो उन्हें निर्भीक होकर पुलिस के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए और तथ्यों के साथ सच्चाई सामने लानी चाहिए।

संदीप खत्री ने कहा कि अनर्गल, बेबुनियाद और झूठे आरोपों का समाज में कोई आधार नहीं होता। ऐसे आरोप न केवल व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि प्रदेश की जनता को भी गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आरोपों में वास्तव में कोई सच्चाई है, तो कानून के दायरे में आकर उसे साबित किया जाए, न कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जाए।

पत्रकार वार्ता के दौरान समाजसेवी पुरुषोत्तम शर्मा ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर अपने आरोपों में सच्चे हैं, तो उन्हें बिना देरी किए सामने आना चाहिए और सबूत प्रस्तुत करने चाहिए। पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि यदि लगाए गए आरोप सही साबित हो जाते हैं, तो वे स्वयं जलसमाधि लेने तक के लिए तैयार हैं।

दोनों वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई चाहे जिस पक्ष में हो, उसे कानून के माध्यम से सामने आना चाहिए, ताकि समाज में फैल रही भ्रांतियों और दुष्प्रचार पर विराम लग सके।

जश्ने विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम जन्म दिवस धूमधाम से मनाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। इमाम बाड़ा अहबाब नगर में मौला अली अलैहिस्सलाम का जन्म दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंजुमन फ़रोग़ ए अज़ा ज्वालापुर के संयोजन में आयोजित मौला अली अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस पर महफ़िल ए मुशायरा का आयोजन किया गया।

संस्था के अध्यक्ष हैदर नक़वी ने बताया के इस्लामिक केलिन्डर के हिसाब से मौला अली अलैहिस्सलाम का जन्म दिन पैगंबर मुहम्मद के दामाद मौला अली अलैहिस्सलाम के जन्म का प्रतीक है। मौला अली अलैहिस्सलाम का जन्म 13 रजब को मक्का के काबा में हुआ था, जो दुनिया में किसी के जन्म के लिए एक अनोखी घटना है। हैदर नकवी ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम इस्लामी दुनिया में एकता को ख़ास अहमियत देते थे। इसको वह अल्लाह की अनुकंपा और उसकी रहमत मानते थे। मौला अली का कहना था कि समाज की भलाई संगठित रहने में ही है। इस बारे में उनका कहना है कि इस बात के मद्देनज़र कि अल्लाह भी संगठन या एकता के साथ है मुसलमानों को एकजुट रहते हुए अपनी एकता की सुरक्षा करनी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम समाज या क़ौम में मतभेदों से होने वाले नुक़सान को स्पष्ट करते हुए इसकी उपमा उस भेड़ से देते हैं जो अपने रेवड़ से अलग हो गई है और अब वह चरवाहे से दूर हो चुकी है। इस आधार पर आदमी को संगठित समाज से अलग नहीं होना चाहिए। मुशायरे में बिलाल रज़ा, हैदर नक़वी, जाफ़र रज़ा, ज़हूर हसन, शमीम, अली रज़ा, इक़्तेदार नक़वी कलाम पेश किए। मुशायरे में फ़िरोज़ ज़ैदी, एहतेशाम अब्बास, जोनी, मुदस्सिर हुसैन, हाजी अमान ख़ान, ज़ीशान, यूसुफ, शब्बू अंसार, मुनीर, हसीन, समर, जुनैद, साहिल, कैफ, अली रज़ा, जाफ़र, कय्यूम, बिलाल, शमीम, इक़बाल, सग़ीर, फरहान, सुभान अली, नावेद, मोहसिन, तुराब, श्यान, शहज़ाद आदी ने कलाम पेश किए। मोहम्मद अली, दानिश आब्दी, ज़हूर हसन, खत्ताब, उमैर, फरात, समीर, इख़राज, फैसल, फैसल अली, क़ादिर आदि शामिल रहे।

नगरायुक्त नंदन कुमार की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सराहनीय पहल

● बाजारों में रात्रिकालीन व्यवस्था पर फोकस, निरंतर मानिटरिंग के निर्देश ● नगर निगम क्षेत्र के नालों की सफाई शुरू कराने के दिये निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

धर्मनगरी हरिद्वार के नगर क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त नंदन कुमार (IAS) ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित कर समस्त सफाई निरीक्षकों और मुख्य सफाई निरीक्षकों को दिशा निर्देश दिये। नगर आयुक्त ने समस्त वार्डों में नाला सफाई अभियान को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक मुख्य सफाई निरीक्षक अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आंकलन हो सके। नगर क्षेत्र के बाज़ार क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों के पश्चात स्वच्छता बनी रहे। इसके अतिरिक्त नालों पर अतिक्रमण हटाने के लिए वार्ड पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा गया, ताकि जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो। नगर आयुक्त ने बैठक के अंत में स्पष्ट किया कि स्वच्छता से जुड़ी किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए हरिद्वार को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर विशेष फोकस

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की गाइडलाइंस के अनुरूप Bulk Waste Generators (बड़े कचरा उत्पादक) को चिन्हित कर उनका रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

संबंधितों को निर्देशित किया गया कि Bulk Waste Generators द्वारा केवल ड्राई वेस्ट ही नगर निगम को सौंपा जाएगा। वेट वेस्ट का निस्तारण अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा।

डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं मानव संसाधन

प्रत्येक मुख्य सफाई निरीक्षक को अपने वार्ड में डोर-टू-डोर कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे यूजर चार्ज एवं उनके लक्ष्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, प्रत्येक सफाई निरीक्षक को अपने वार्ड में कम पड़ रहे पर्यावरण मित्रों के संबंध में तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी

आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम हरिद्वार के प्रदर्शन में सुधार हेतु स्वच्छता ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक शौचालयों की दैनिक मॉनिटरिंग अनिवार्य की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की गाइडलाइंस के अनुसार शौचालयों में मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स पर कार्रवाई

बैठक के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले तीन महीनों में नगर निगम हरिद्वार द्वारा विभिन्न स्थलों पर सॉलिड वेस्ट के ब्लैक स्पॉट्स/गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को समाप्त किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से आर्य नगर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, शंकर आश्रम के निकट गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, आनन्दवाला बाग में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, अपर रोड पर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, भीमगोडा में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट और कड़च्छ क्षेत्र का गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट शामिल है। नगरायुक्त ने समस्त सफाई निरीक्षकों को अपने-अपने वार्डों में ऐसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए गए।

ये अधिकारी रहे बैठक में उपस्थित

बैठक में उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त ऋषभ उनियाल, मुख्य सफाई निरीक्षक अर्जुन चौधरी, मनोज कुमार, धीरेंद्र सेमवाल, विकास चौधरी, श्रीकांत, सुनील कुमार, संजय शर्मा, विकास छाचर तथा सुरेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध गिरफ्तार, एक-एक अवैध चाकू बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान सिडकुल पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध चाकू बरामद हुए। सिडकुल पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक-एक अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों के विरुद्ध थाना सिडकुल पर मु0अ0सं0 02/2026, मु0अ0सं0 03/2026 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपितों के नाम विशाल पुत्र मुकेश, निवासी जगन वाला, हलदौर, जनपद बिजनौर, हाल पता प्रीत विहार कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, थाना सिडकुल और पंकित पुत्र बाबूराम, निवासी रावली महदूद, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार है।

रुड़की पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक आरोपी किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रुड़की पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बांदा रोड क्षेत्र में जीशान उर्फ मदी द्वारा अवैध रूप से भैंस वंशीय पशु का कटान किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सूचना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा एक पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। मौके से लगभग 215 किलोग्राम भैंस वंशीय मांस एवं कटान में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। मौके से व्यक्ति जीशान उर्फ मदी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

टीवी कलाकार अर्जुन बिजलानी ने लगायी मां गंगा में आस्था की डुबकी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पौष पूर्णिमा तथा माघ स्नान शनिवार से प्रारंभ हो गया है। ऐसे में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार अर्जुन बिजलानी ने भी हरिद्वार पहुंच कर गंगा स्नान किया। उन्होंने वीआईपी घाट पर गंगा स्नान किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित उज्वल पंड़ित ने उन्हे गंगा पूजन कराया। ऋषिकेश क्रिएटिव प्रोडक्शन के ऑनर चिन्मय पंडित के साथ अर्जुन बिजलानी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बताया कि निजी कार्य से देहरादून आये थे, शाम को ही उनकी फ्लाइट है। मेरे पास समय भी था तो चिन्मय से चर्चाओं के बीच गंगा स्नान का मन बन बैठा। अर्जुन ने जानकारी साझा करते हुए बताया एक बार बनारस शूटिंग के दौरान भी जब वहां गए थे तो वह दिन गंगा दशहरा का बड़ा दिन था और आज भी पौष पूर्णिमा जैसा बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहुंचकर वाकई बहुत शांति मिलती है। श्रद्धालुओं से भी अपील की विश्व प्रसिद्ध हरकी पैडी पर आप भी जरूर आये। इस मौके पर श्री गंगा सभा सचिव उज्वल पंडित ने अर्जुन बिजलानी रुद्राक्ष माला पहनाकर स्वागत किया। तीर्थ पुरोहित उज्वल पंड़ित का कहना है कि अब टीवी और सिने कलाकार भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सेलेब्रिटी भी अब गंगा स्नान के लिए हर मौसम में हरिद्वार आ रहे हैं।

हरिद्वार पुलिस का रिपोर्ट कार्ड: बीते साल में अपराधियों पर हुआ करारा प्रहार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोबाल की कड़क नीति के असर के चलते बीता साल अपराधियों पर भारी पड़ा। *अपराधियों के लिए हरिद्वार पुलिस काल बनकर सामने खड़ी रही। बड़ी संख्या में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। नशे के सौदागरों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। इस अवधि में हरिद्वार पुलिस ने जनपद में 585 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजकर नशे का साम्राज्य ध्वस्त करने का कार्य किया।

हरिद्वार पुलिस की साईबर सेल ने वर्ष 2025 में प्राप्त हुए साइबर ठगी की कुल 5781 प्राप्त शिकायतों में से 4356 शिकायतों को निस्तारित करते हुए फ्रॉड का शिकार बने लोगों की कुल ?1,27,458,64/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ चौसठ रुपये) वापस दिलाए। इस दौरान सभी थानों एवं साईबर सेल ने मिलकर ष्ट्रक्श्वढ्ढक्र पोर्टल की मदद से कुल 1088 मोबाइल फोन रिकवर किए तथा उक्त मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया। रिकवर किए गए मोबाइल फोनों की बाजार कीमत ?1,65,000,00/- (एक करोड़ पैसठ लाख रुपए) के करीब आंकी गई।

गुमशुदगी/ अपहरण के कुल 1320 मामलों में पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए 1082 गुमशुदाओं/अपहृत को सकुशल बरामद किया। इनमें 263 किशोरियां, 105 किशोर, 420 महिलाएं तथा 294 पुरुष शामिल हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने वर्ष 2025 में कुल 5300 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 508 आरोपित को गिरफ्तार किया गया तथा 307 आरोपित के खिलाफ चालानी/नोटिस की कार्यवाही की गई। इनमें विवाह के नाम पर छल, पहचान, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति छिपाकर उत्प्रेरित करने के 04 तथा फर्जी सौशल मीडिया प्रोफाइल, फिशिंग आदि साईबर धोखाधड़ी के 26 आरोपी शामिल हैं।

गौवंश तस्करी और गौहत्या से जुड़े तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए उत्तराखण्ड गौ संरक्षण अधिनियम के तहत बीते वर्ष कुल 400 आरोपित के खिलाफ 127 मुकदमें दर्ज किए गए। 48 पशु बरामद करने के साथ 15768 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 116 आरोपित के खिलाफ 65 मुकदमें दर्ज करते हुए 66 जीवित पशु व 3102 किलोग्राम भैंसवंशीय मांस बरामद किया गया।

घटित अपराधों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए हरिद्वार पुलिस ने इस दौरान हत्या के 62 मुकदमों का खुलासा करते हुए कुल 104 आरोपित को गिरफ्तार किया। समय समय पर चलाए गए चैकिंग अभियानों के दौरान अवैध अस्लाह के 393 आरोपित को गिरफ्तार कर 02 डीबीबीएल राइफल, 06 एसबीबीएल, 195 तमंचे, 02 रिवाल्वर, 12 पिस्टल, 244 कारतूस तथा 364 चाकू बरामद किए।

नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए हरिद्वार पुलिस ने वर्ष 2025 में 585 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट में 536 मुकदमें दर्ज किये। इस दौरान 16.83 किलोग्राम चरस, 5.53 किलोग्राम स्मैक, 1.18 किलोग्राम अफीम, 243.94 किलोग्राम गांजा, 14075 नशीली गोलियां, 3906 नशीले इंजेक्शन, 353843 कैप्सूल व 326 सीरप बरामद किया गया। उक्त बरामद नशीले पदार्थो की बाजार कीमत 179300000/- (सत्रह करोड़ तेरानवे लाख) के करीब आंकी गई है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान हरिद्वार पुलिस ने 988 आरोपित को गिरफ्तार करते हुए 976 मुकदमें दर्ज किए गए। इस दौरान बरामदगी 12392 बोतल देशी शराब, 3523 बोतल अंग्रेजी शराब, 2877 लीटर कच्ची शराब, 760 बीयर व 08 भट्टी एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए।

संपादकीय

सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की कमजोर होती याददाश्त

डिजिटल युग ने जीवन को जितना आसान बनाया है, उतनी ही गंभीर चुनौतियाँ भी समाज के सामने रख दी हैं। खासकर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बच्चों की मानसिक सेहत और याददाश्त पर नकारात्मक असर डाल रहा है, जो अब एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बन चुका है। मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इनका अनियंत्रित उपयोग बचपन की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है।

आज का बच्चा खेल के मैदान, किताबों और रचनात्मक गतिविधियों से अधिक समय स्क्रीन के सामने बिता रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स, शॉर्ट वीडियो और तेजी से बदलती जानकारियाँ बच्चों के मस्तिष्क को त्वरित उत्तेजना की आदत डाल रही हैं। इसका सीधा असर उनकी एकाग्रता पर पड़ता है। जब दिमाग कुछ सेकंड से ज्यादा किसी विषय पर टिक नहीं पाता, तो पढ़ी हुई बातों को याद रखना कठिन हो जाता है।

याददाश्त का सीधा संबंध ध्यान और सोचने की क्षमता से होता है। सोशल मीडिया बच्चों को सोचने की बजाय देखने और तुरंत प्रतिक्रिया देने का आदी बना रहा है। हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होने के कारण दिमाग पर याद रखने का दबाव कम हो गया है। परिणामस्वरूप स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है और पढ़ाई में रुचि घट रही है।

इसके साथ ही सोशल मीडिया बच्चों की नींद पर भी बुरा असर डाल रहा है। देर रात तक मोबाइल देखने से नींद पूरी नहीं हो पाती, जबकि अच्छी याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए पर्याप्त और गहरी नींद बेहद जरूरी है। नींद की कमी बच्चों में चिड़चिड़ापन, थकान और भूलने की समस्या को और बढ़ा देती है।

इस स्थिति में अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा, पढ़ने की आदत, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना समय की मांग है। स्कूलों को भी डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ मानसिक संतुलन और एकाग्रता पर ध्यान देना होगा।

यह कहना उचित नहीं होगा कि सोशल मीडिया पूरी तरह हानिकारक है। सही दिशा और सीमित उपयोग से यह ज्ञान और सीखने का माध्यम बन सकता है। समस्या इसके असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग की है।

सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की कमजोर होती याददाश्त एक चेतावनी है। यदि समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया, तो आने वाली पीढ़ी सूचनाओं से भरी तो होगी, लेकिन सोचने और याद रखने की क्षमता में कमजोर रह जाएगी।

इन्दौर की जल-त्रासदी और प्रशासनिक लापरवाही का नंगा चेहरा

ललित गर्ग

स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें कथनी और करनी की असमानता की पोल खोलती भयावह लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है और न ही इसे तकनीकी खामी कहकर टाला जा सकता है। यह घटना उस व्यवस्था का क्रूर और नंगा सच है, जो स्वच्छता के तमगों से सजी हुई है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। जिस शहर को लगातार सात वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल के कारण पंद्रह निर्दोष लोगों की मौत हो जाना पूरे तंत्र पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। यह त्रासदी साबित करती है कि चमकदार रैंकिंग और पुरस्कार जीवन की वास्तविक सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकते। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर का पानी मिल गया, जिससे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। सौ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए, सैकड़ों बीमार पड़े और अनेक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। सभ्य समाज में यह कल्पना ही आत्मग्लानि से भर देने वाली है कि जिस पानी को जीवनदायिनी मानकर पिया गया, वही सीवर की गंदगी से मिला हुआ था।

सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। नागरिकों ने पहले ही दूषित पानी की शिकायतें की थीं। पानी के रंग, गंध और स्वाद में बदलाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन नगर निगम, जलप्रदाय विभाग और स्वास्थ्य तंत्र कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। प्रशासन तब हरकत में आया जब मौतें हो चुकी थीं। यह लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी संस्थागत असंवेदनशीलता, क्रूरता एवं अमानवीयता है। यह उस प्रशासनिक संस्कृति का परिणाम है जिसमें फाइलें और औपचारिकताएं मानव जीवन से अधिक मूल्यवान हो गई हैं। सवाल यह नहीं है कि पानी में सीवर कैसे मिला, असली सवाल यह है कि चेतावनियों के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं गया? हर बार की तरह इस बार भी जांच समितियां बनीं, मुआवजे की घोषणाएं हुईं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। भले ही अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन, क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देतीं, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती हैं। क्या इन दिखावे की कार्रवाइयों से मृतकों का प्रायश्चित हो गया? क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? सच्चाई यह है कि जांच समितियां अब जवाबदेही तय करने का नहीं, बल्कि मामले को ठंडा करने का माध्यम बन चुकी हैं।

इस दुखद घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने लोगों के घावों को और गहरा किया। जिस क्षेत्र में यह त्रासदी घटी, उसके प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का विभाग आता है, उनकी असंवेदनशील टिप्पणियों ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया। बाद में खेद प्रकट किया गया, लेकिन सवाल यह है कि खेद से क्या उन परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? यह सही है कि उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेत्री ने दोषियों से प्रायश्चित और दंड की मांग की, लेकिन देश का अनुभव बताता है कि ऐसी मांगें अक्सर समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार का खूब प्रचार किया जाता है, लेकिन इंदौर की घटना ने दिखा दिया कि यदि व्यवस्था की पटरियां जर्जर हों, तो इंजन कितने भी हों, दुर्घटना तय है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण की बात कही थी और जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया था।

बदलते समाज, कानून और अपराध की नई तस्वीर

कांतिलाल मांडोत

भारतीय जेलों में महिला कैदियों की संख्या में आई तेज़ बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना में आए गहरे बदलावों का संकेत है। हाल में जारी इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च आईसीपीआर की रिपोर्ट वर्ल्ड फीमेल इम्प्रिजनमेंट लिस्ट बताती है कि पिछले दो दशकों में भारतीय जेलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों और सामान्य जनसंख्या की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 2000 में जहां महिला कैदियों की संख्या 9,089 थी, वहीं 2022 तक यह बढ़कर 23,772 हो गई। यह 162 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि इसी अवधि में पुरुष कैदियों की संख्या 77 प्रतिशत बढ़ी और देश की कुल आबादी में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा अपराध करने लगी हैं, या फिर कानून और समाज की नजर महिलाओं पर पहले से अधिक सख्त हो गई है। क्या यह बदलाव महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी का अनचाहा परिणाम है, या फिर सामाजिक-आर्थिक दबावों का असर है। इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि महिला अपराध और महिला कैदियों की बढ़ती संख्या समाज के स्वास्थ्य का आईना होती है।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में भारतीय समाज की संरचना अपेक्षाकृत पारंपरिक थी। महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर-परिवार तक सीमित मानी जाती थी। शिक्षा और रोजगार में उनकी भागीदारी सीमित थी और सार्वजनिक जीवन में उनकी मौजूदगी कम दिखाई देती थी। उस दौर में महिला अपराध की घटनाएं कम थीं और जो मामले सामने आते भी थे, वे अधिकतर घरेलू विवाद, पारिवारिक झगड़े या परिस्थितिजन्य अपराधों से जुड़े होते थे। समाज और कानून दोनों ही महिलाओं को अपराधी के रूप में देखने से कतराते थे। यह धारणा प्रचलित थी कि महिला अपराध स्वभाव से नहीं, बल्कि मजबूरी या किसी पुरुष के प्रभाव में होता है।

न्यायिक व्यवस्था में भी महिलाओं के प्रति एक प्रकार की नरमी देखने को मिलती थी। जमानत, सजा और विचाराधीन मामलों में महिलाओं को अक्सर राहत मिल जाती थी। सामाजिक सोच यह मानती थी कि महिला को सुधार की जरूरत है, न कि कठोर दंड की। यही वजह थी कि महिला कैदियों की संख्या लंबे समय तक सीमित रही।

लेकिन इक्कीसवीं सदी के साथ भारत तेजी से बदला। शहरीकरण, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण ने सामाजिक ढांचे को नई दिशा दी। महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यापार और राजनीति में आगे बढ़ीं। उन्होंने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां संभालीं। यह बदलाव सकारात्मक था और आज की महिला पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनी। लेकिन इसी बदलाव के साथ अपराध की दुनिया का स्वरूप भी बदला और महिलाओं की भूमिका उसमें बढ़ने लगी।

आईसीपीआर रिपोर्ट के अनुसार, आज महिलाएं संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध और साइबर अपराध जैसे मामलों में अधिक संख्या में सामने आ रही हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि अपराध अब केवल हाशिए पर खड़े लोगों की मजबूरी नहीं रहा, बल्कि एक संगठित और नेटवर्क आधारित गतिविधि बन चुका है। इन नेटवर्कों में महिलाओं को कम संदेहास्पद मानकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वे अपराध के जाल में फंस जाती हैं।

इसके साथ ही न्यायिक रुझान में भी बड़ा बदलाव आया है। कानून के सामने समानता के सिद्धांत को अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब महिला और पुरुष अपराधियों के बीच भेदभाव कम हुआ है। जहां पहले महिला होने के कारण राहत मिल जाती थी, वहीं अब अपराध की प्रकृति के आधार पर सजा तय की जा रही है। यह समानता जरूरी है, लेकिन इसका असर आंकड़ों में महिला कैदियों की संख्या बढ़ने के रूप में भी दिख रहा है। महिला अपराध के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और असमान विकास ने समाज के कमजोर वर्गों पर दबाव बढ़ाया है। महिलाएं, खासकर शहरी झुग्गियों और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। रोजगार के सीमित अवसर और कम आय उन्हें अवैध गतिविधियों की ओर धकेल देते हैं। कई मामलों में महिलाएं अपराध की मुख्य योजनाकार नहीं होतीं, बल्कि किसी बड़े गिरोह का हिस्सा बन जाती हैं। पारिवारिक और सामाजिक टूटन भी एक बड़ा कारण है। संयुक्त परिवारों का विघटन, घरेलू हिंसा, तलाक और अकेलेपन ने महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर किया है। कई महिलाएं अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए गलत रास्ते चुन लेती हैं। इसके अलावा शिक्षा और कानूनी जागरूकता की कमी भी महिला अपराध को बढ़ावा देती है। कई बार महिलाएं यह समझ ही नहीं पातीं कि वे जिस गतिविधि में शामिल हैं, वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

हाल के वर्षों में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सघन अभियानों के कारण भी महिला कैदियों की संख्या बढ़ी है। अनुमान के अनुसार, केवल पश्चिम बंगाल की जेलों में 358 बांग्लादेशी महिलाएं कैद हैं। यह स्थिति सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और मानव तस्करी जैसे मुद्दों को भी उजागर करती है। इन महिलाओं में से कई तस्करी का शिकार होती हैं, लेकिन कानून की नजर में वे अपराधी बन जाती हैं।

महिला कैदियों की बढ़ती संख्या ने जेल प्रशासन के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पुरुष प्रधान जेल व्यवस्था महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने में अभी भी पीछे है। गर्भवती महिला कैदियों, बच्चों के साथ रहने वाली महिलाओं, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। जेलों में पुनर्वास और सुधार की व्यवस्था कमजोर होने के कारण कई महिलाएं जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में लौट जाती हैं।

इस समस्या का समाधान केवल सख्त कानून या ज्यादा जेलें बनाकर नहीं निकाला जा सकता। महिला अपराध को समझने के लिए हमें समाज की जड़ों तक जाना होगा। महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। जब महिलाओं के पास सम्मानजनक आजीविका के साधन होंगे, तो वे अपराध की ओर कम आकर्षित होंगी। इसके साथ ही कानूनी जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि महिलाएं अनजाने में अपराध का हिस्सा न बनें। संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी में महिलाओं का इस्तेमाल करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वालों को कानून का कड़ा संदेश मिलना जरूरी है।

फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार विजेता -अर्लेंगर जोसेफ

संजय गोस्वामी

अर्लेंगर जोसेफ अर्लेंगर का जन्म 5 जनवरी, 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, में हुआ जोसेफ अर्लेंगर का जन्म सैन फ्रांसिस्को में जर्मन अप्रवासियों के परिवार में हुआ था, जिसमें वह अकेले ऐसे थे जिन्होंने शुरुआती शिक्षा से आगे पढ़ाई की। उन्होंने 1894 में कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी (बर्कले) से ग्रेजुएशन किया। वह स्थानीय कूपर मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने वाले थे, तभी उन्हें बताया गया कि जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (बाल्टीमोर) का नया मेडिकल स्कूल बाकी सभी से बेहतर बनने का लक्ष्य रखता है, और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाद में विलियम एच हॉवेल (1860-1945) ने उन्हें एकेडमिक जीवन में करियर के लिए गाइड किया। समय के साथ उन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी (मैडिसन) और सेंट लुइस, मिसौरी में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी के चेयर पद संभाले।ग्रेजुएशन के बाद, अर्लेंगर ने विलियम ओस्लर के अंडर जॉन्स हॉपकिन्स हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की और एक फिजियोलॉजी लैब में काम किया। अर्लेंगर ने स्कूल में पाचन और मेटाबॉलिज्म पर लेक्चर भी दिए। अर्लेंगर को कार्डियोलॉजी में भी दिलचस्पी थी, खासकर जिस तरह से एक्साइटेशन एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है, और उन्होंने आर्थर हिर्शफेल्डर के साथ रिसर्च किया। अर्लेंगर ने एक नए तरह का स्फिग्मोमैनोमीटर बनाया और पेटेंट कराया जो ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर माप सकता था। 1901 में जॉन्स हॉपकिन्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करते हुए, अर्लेंगर ने कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर ने जॉन्स हॉपकिन्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर विलियम हेनरी हॉवेल का ध्यान खींचा। हॉवेल ने अर्लेंगर को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भर्ती किया। 1906 से कुछ समय पहले अर्लेंगर को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया। 1906 में, अर्लेंगर ने मैडिसन में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी के पहले चेयर के रूप में पद स्वीकार किया। 1910 में, वह सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद लेने के लिए चले गए; सेंट लुइस के पद से अर्लेंगर को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा फंडिंग मिली। हर्बर्ट स्पेंसर गैसर, जो विस्कॉन्सिन में अर्लेंगर के पूर्व छात्र थे, इस कदम के तुरंत बाद अर्लेंगर की लैब में शामिल हो गए। पहले विश्व युद्ध के दौरान, दोनों ने शॉक के प्रभावों की जांच करने के रिसर्च में योगदान दिया।इस काम के हिस्से के रूप में, अर्लेंगर हिस के बंडल को क्लैंप करके और कसकर एक जानवर मॉडल में हार्ट ब्लॉक पैदा करने में सक्षम थे।साथ में, वे 1922 में एक बुलफ्रॉग की साइटिक नर्व के एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने में कामयाब रहे और अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में परिणाम पब्लिश किए। यह अनिश्चित है कि दोनों की दिलचस्पी न्यूरोसाइंस में इतनी अचानक क्यों बदल गई, क्योंकि अर्लेंगर पहले से ही कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक रूप से सम्मानित थे। अर्लेंगर को 1922 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और 1927 में अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी के लिए चुना गया था। अर्लेंगर और गैसर एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ऑसिलोस्कोप को कम वोल्टेज पर चलाने के लिए मॉडिफाई करने में सक्षम थे। इस मॉडिफिकेशन से पहले, न्यूरल एक्टिविटी को मापने का एकमात्र तरीका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ था, जो केवल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा सकता था। इस टेक्नोलॉजी से, वे यह देख पाए कि एक्शन पोटेंशियल दो फेज़ में होते हैं–एक स्पाइक (शुरुआती तेज़ी) जिसके बाद एक आफ्टर-स्पाइक (पोटेंशियल में धीमे बदलावों का एक क्रम) होता है।उन्होंने पाया कि न्यूरॉन्स कई रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें से हर एक में एक्साइटेबिलिटी की अपनी क्षमता होती है। इस रिसर्च से, दोनों ने पाया कि एक्शन पोटेंशियल की वेलोसिटी नर्व फाइबर के डायमीटर के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। यह पार्टनरशिप 1931 में खत्म हो गई, जब गैसर ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक पद स्वीकार कर लिया।1944 में, उन्हें इन खोजों के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला। वे एक अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें (हर्बर्ट गैसर के साथ) 1944 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यह पता लगाने के लिए कि एक ही तंत्रिका कॉर्ड के अंदर के फाइबर के अलग-अलग कार्य होते हैं। तंत्रिका कार्य पर अर्लेंगर का शोध गैसर के साथ एक फायदेमंद सहयोग का नतीजा था, जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, मैडिसन (1906-10) में उनके छात्रों में से एक थे। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेंट लुइस (1910-46) में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अर्लेंगर की नियुक्ति के तुरंत बाद, गैसर भी उनसे वहीं जुड़ गए, और उन्होंने उन तरीकों का अध्ययन करना शुरू किया जिनसे हाल ही में विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को फिजियोलॉजिकल जांच में लागू किया जा सके।

पीएम-श्री विद्यालयों के 977 मेधावी छात्र जाएंगे अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर

वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे छात्र, 3.06 करोड़ रुपये स्वीकृत

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रदेश के पीएम-श्री विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सूबे के 207 पीएम-श्री विद्यालयों के कुल 977 मेधावी छात्र-छात्राओं को अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 6 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आगामी 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस शैक्षिक भ्रमण के दौरान

छात्र-छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों में स्थित नेशनल साइंस सेंटर, आईआईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, सांस्कृतिक एवं विरासत स्थल तथा कला एवं संगीत अकादमियों का भ्रमण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, शैक्षिक और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कुल 1048 प्रतिभागी इस भ्रमण में सम्मिलित होंगे, जिनमें 977 छात्र-छात्राएं, 13 नोडल अधिकारी तथा 58 शिक्षक-शिक्षिकाएं एस्कॉर्ट के रूप में शामिल रहेंगे। जनपदवार देखें तो अल्मोड़ा से 104, बागेश्वर 36, चमोली 96, चम्पावत 56, देहरादून 66, हरिद्वार 76, नैनीताल 104, पौड़ी 51, पिथौरागढ़ 81, रुद्रप्रयाग 31, टिहरी 71, ऊधमसिंह नगर 144 तथा उत्तरकाशी से 61 छात्र-छात्राएं इस शैक्षिक भ्रमण का हिस्सा होंगे।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु प्रत्येक पीएम-श्री विद्यालय से दो छात्र एवं दो छात्राओं का चयन किया जाएगा, जो कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत हों तथा वर्ष 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में भारत भ्रमण कार्यक्रम में भाग लिया है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

भ्रमण दल को जनपद स्तर पर सांसद, विधायक अथवा जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने तथा भ्रमण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से परिचित कराना है, ताकि उनमें नवाचार, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो सके।

एक नजर

216 जनसेवा कैम्प, 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ, धामी सरकार का सुशासन मॉडल बना मिसाल

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित समाधान का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। 3 जनवरी 2026 की दैनिक प्रगति रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सरकार योजनाओं और सेवाओं को फाइलों से निकालकर सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाने में निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 216 जनसेवा कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1,44,134 नागरिकों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की है। केवल आज के दिन आयोजित 12 कैम्पों में 8,940 लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरोसा इस कार्यक्रम पर लगातार मजबूत हो रहा है। इन कैम्पों के माध्यम से दूरस्थ, पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को पहली बार एक ही मंच पर समस्याओं के समाधान और सरकारी सेवाओं की सुविधा मिली है। कार्यक्रम के दौरान अब तक 18,360 शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,068 मामलों का निस्तारण मौके पर अथवा त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से किया जा चुका है। केवल आज के दिन 613 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 292 का तत्काल समाधान किया गया। शेष प्रकरणों को भी समयबद्ध कार्ययोजना के तहत संबंधित विभागों को भेजकर निरंतर निगरानी में रखा गया है। इसी क्रम में आय, जाति, निवास, सामाजिक श्रेणी सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए अब तक 24,081 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,808 आवेदन आज दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट है कि आम नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों के लिए अब सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सेवाओं को जनता के निकट लाने की यह पहल विशेष रूप से गरीब, वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 80,712 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा चुका है, जिनमें 3,509 लाभार्थी आज शामिल हुए। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर सरकार ने पारदर्शिता और जनसुविधा को नई मजबूती दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम उत्तराखण्ड में शासन की कार्यसंस्कृति को बदलने वाला अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के बीच जाकर समाधान सुनिश्चित करे। यह कार्यक्रम आज उत्तराखण्ड में सुशासन की नई पहचान बन चुका है और आने वाले समय में राज्य के समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

दो शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की पूर्व छात्रा से मोबाइल फोन के माध्यम से आपत्तिजनक बातचीत करने के आरोप में दो शिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले स्कूल प्रबंधन ने आंतरिक जांच के बाद दोनों शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दी थी। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, शहर के एक नामी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक की ओर से चार वर्ष पहले स्कूल छोड़ चुकी एक छात्रा से मोबाइल पर चैटिंग की जा रही थी। हाल ही में छात्रा ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें बातचीत से जुड़े स्क्रीनशॉट भी बताए जा रहे हैं। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आंतरिक जांच समिति गठित की। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्कूल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों शिक्षकों को पद से हटा दिया।

बताया जा रहा है कि छात्रा ने अब सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट हटा ली है और फिलहाल पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची है। इधर, इस मामले में शुक्रवार रात रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सूखी नदी व्यापार मंडल इकाई का गठन, नीरज पाल अध्यक्ष व प्रमोद गोस्वामी महामंत्री नियुक्त

पथ प्रवाह, हरिद्वार

प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों को संगठित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए सूखी नदी व्यापार मंडल इकाई का गठन किया गया। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने नवगठित इकाई की घोषणा करते हुए पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक की। इसमें नीरज पाल को अध्यक्ष, प्रमोद गोस्वामी को महामंत्री, अमन को कोषाध्यक्ष, दिलीप कुमार एवं रमेश को उपाध्यक्ष, विजय कुमार को सचिव तथा मधुकांत गिरी को जिला सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्षेत्रीय पार्षद महावीर वशिष्ठ को इकाई का संरक्षक नियुक्त किया गया।

प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डा. विशाल गर्ग के नेतृत्व में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डा. विशाल गर्ग ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल व्यापारियों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि उनके हितों की मजबूती से पैरवी करना है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारी निरंतर प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ रहे हैं

और शीघ्र ही पूरे शहर में इकाइयों का गठन कर एक विशाल और सशक्त संगठन खड़ा किया जाएगा।

डा. विशाल गर्ग ने उत्तरी हरिद्वार को यात्री बाहुल्य क्षेत्र बताते हुए मेला प्रशासन से स्थायी विकास कार्य कराने की मांग की, जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल सके।

नवगठित इकाई के अध्यक्ष नीरज पाल और महामंत्री प्रमोद गोस्वामी ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा व्यापारी हितों के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश सचिव मयंक मूर्ति भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार कश्यप, शहर अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शहर महामंत्री विमल सक्सेना, शहर कोषाध्यक्ष अनुज गुप्ता, तहसील कोषाध्यक्ष मनोज सिरोही, निशा गुप्ता, रचना बत्रा, हरीश मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी पर धामी सरकार का बड़ा प्रहार, 2003 से अब तक प्रदेशव्यापी जांच के आदेश

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखंड में परिवार/कुटुंब रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेशभर में व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारियों के पास सुरक्षित रखी जाएं, ताकि अभिलेखों में छेड़छाड़ की कोई संभावना न रहे। इसके साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ/एडीएम स्तर से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा गया है, जिससे पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान की जा सके।मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण एवं प्रतिलिपि सेवाएं पंचायत राज (कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के अंतर्गत संचालित होती हैं। नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही प्रविष्टियों के शुद्धिकरण एवं नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया का प्रावधान भी नियमों में निहित है, जिसे अब और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्राप्त है, जबकि इससे संबंधित अपील उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष की जा सकती है। वर्तमान में यह सेवाएं 'अपणी सरकार' पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि बीते वर्षों में राज्य की सीमा से लगे मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की शिकायतें मिली हैं, जिससे प्रदेश के जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई। इसी के मद्देनज़र सरकार ने परिवार रजिस्टर से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की है। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में परिवार रजिस्टर से संबंधित सेवाओं के लिए प्रदेशभर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन आए, जिनमें से 2,60,337 स्वीकृत किए गए, जबकि 5,429 आवेदन नियमों के उल्लंघन एवं अपूर्ण दस्तावेजों के कारण निरस्त किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि निरस्त आवेदनों की संख्या फर्जी प्रविष्टियों की आशंका की ओर इशारा करती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों सहित प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जांच की जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव या ढिलाई न हो। साथ ही भविष्य में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट नीति के तहत नियंत्रित कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक में सचिव गृह शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ, डीजीपी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार, विशेष सचिव पंचायती राज डॉ. पराग धकाते तथा निदेशक पंचायती राज निधि यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने महिलाओं को बांटे प्रमाण पत्र

क्लाउड किचन का प्रशिक्षण हुआ पूरा, अब गंगा रसोई से होगी पहचान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं पीएनबी शताब्दी ग्राम विकास न्यास के सहयोग से महिलाओं को दिया गया क्लाउड किचन का प्रशिक्षण शनिवार को सम्पन्न हो गया। महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सीडीओ के निर्देशन में की गई क्लाउड किचन की पहल से रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। समापन अवसर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र दिये।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी महिलाओं ने कड़ी मेहनत और लगन से क्लाउड किचन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अब वह अपने किचन से ही खाना तैयार कर उपभोक्ताओं को उनका मनपसंद खाना उपलब्ध करा सकेंगी। इससे महिलाओं को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे तथा उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार प्रदेश का पहला जनपद है जहां महिलाओं को क्लाउड किचन का प्रशिक्षण दिया गया। कहा कि जनपद में कई औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान संचालित हैं, जिसमें काम करने वाले लोगों और अध्ययनरत छात्रों को क्लाउड किचन के माध्यम से घर जैसा और उनकी पसंद का खाना उपलब्ध हो सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि क्लाउड किचन में कार्य कर रही महिलाओं को गंगा रसोई के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा। इसीलिए क्लाउड किचन का नाम गंगा रसोई रखा गया है। इस अवसर पर सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए नलिनीत घिल्डियाल ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी महिलाओं का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। एलडीएम दिनेश गुप्ता ने महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्लाउड किचन शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निदेशक शिव कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक पीएनबी मंडल कार्यालय पुरुषोत्तम प्रसाद, जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन (रीप) संजय सक्सेना, आरएम सिडकुल कमल किशोर, उद्योग विभाग से दिनेश सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

साहिल भदौरिया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, नशे की हेवी डोज देकर दोस्त ने की हत्या

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने साहिल भदौरिया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। आरोपी ने उधार के डेढ़ लाख रुपये से बचने के लिए नशेड़ी युवक ने अपने ही पुराने दोस्त को नशे की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया। मामला 24 दिसंबर 2025 का है।

देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कला शांति मार्ग निवासी वैशाली देवी पत्नी दीपक भदौरिया ने कोतवाली ज्वालापुर में प्रार्थना पत्र देकर अपने 25 वर्षीय पुत्र सहजल उर्फ साहिल भदौरिया के गुमशुदा होने की सूचना दी थी। बताया गया कि सहजल अपने दोस्त के साथ लालपुल ज्वालापुर आया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी संख्या 67/2025 दर्ज कर तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 30 दिसंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि

सहजल उर्फ साहिल का शव लालपुल ज्वालापुर के पास झाड़ियों में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराया। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका स्पष्ट होने पर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 31 दिसंबर 2025 को गुमशुदगी को हत्या के मुकदमे में तरमीम करते हुए मु0अ0सं0-764/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेन्द्र गंगवार को सौंपी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर 2 जनवरी 2026 को पुलिस ने नामजद अभियुक्त आर्य गिरी पुत्र विनोद गिरी निवासी दुर्गा घाट श्मशान घाट रोड, खड़खड़ी कोतवाली नगर हरिद्वार को पुराना रानीपुर मोड़ रेलवे अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह और सहजल पुराने दोस्त थे तथा दोनों पहले कपड़े के व्यापार में साझेदारी कर चुके थे। इसी दौरान दोनों नशे के आदी हो गए और अक्सर इंजेक्शन से एविल व स्मैक का सेवन करते थे। आरोपी पर सहजल के डेढ़ लाख रुपये उधार थे। पैसे लौटाने से बचने के लिए उसने जानबूझकर एविल और स्मैक को मिलाकर एक भारी डोज तैयार की। पहले खुद थोड़ी मात्रा ली और शेष पूरी डोज सहजल को लगा दी। आरोपी को पता था कि इतनी अधिक मात्रा जानलेवा साबित होगी। इसके बाद सहजल बेहोश होकर झाड़ियों में गिर पड़ा। घबराकर आरोपी उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गया।

आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि सहजल की मां और अन्य लोग जब उसके घर पूछताछ के लिए पहुंचे तो उसने डर के कारण सच्चाई छिपाई और स्कूटी की चाबी दे दी। पुलिस पूछताछ के दौरान भी वह सच बताने का साहस नहीं जुटा सका।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से नशे में प्रयुक्त सामग्री बरामद की, जिसमें एक खाली एविल 10 एमएल इंजेक्शन, दो खाली सिरिंज सुई सहित तथा दो प्लास्टिक रैपर शामिल हैं।

मर्डर केस को खुलझाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेन्द्र गंगवार, उप निरीक्षक समीप पाण्डेय, कांस्टेबल अमित गौड व कांस्टेबल राजेश बिष्ट शामिल रहे।

एक नजर

अमित सैनी के निधन पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोकाकुल परिवार से की मुलाकात

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अमित सैनी का असामयिक निधन अत्यंत दुःखद है और यह केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान मिले तथा शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

अमित सैनी के निधन के उपरांत हरिद्वार के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शोकाकुल परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान सांसद ने परिवार के सदस्यों से विस्तार से बातचीत करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में वे और पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अमित सैनी का जीवन सरलता, सद्भाव और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी आवश्यकता या कठिनाई में वे सदैव उनके साथ हैं।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत अमित सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।

स्वच्छ नजर आ रहा हरिद्वार, हट रहा सड़कों से गंदगी का अंबार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए जाने के लिए जनपद में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में लगातार चल रहे स्वच्छता अभियान का 46वां दिन सफलता पूर्वक पूरा हो गया। शहर से लेकर गांव तक चल रहे इस अभियान के बाद सड़कों से भी गंदगी के ढेर साफ होते दिखायी दे रहे हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद वासियों से अपेक्षा की है कि नव वर्ष के अवसर पर सभी संकल्प ले की हम अपने घर आंगन एवं आस पास क्षेत्र को साफ सुथरा रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस माह सफाई अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने अवगत कराया है कि बीएचईएल क्षेत्रांतर्गत आकांक्षा स्कूल सेक्टर 01 एवं मध्य मार्ग पर भेल टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया साथ ही कूड़े को उचित निस्तारण हेतु भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एनएचएआई एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी अपनी सड़कों में चलाया गया सफाई अभियान। अधिशासी अभियंता एनएचएआई अतुल शर्मा ने अवगत

कराया है कि दूधाधारी फ्लाईओवर एवं एनएच 74 क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई का कार्य कराया गया। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुरेश तोमर ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा गांव लक्सर क्षेत्र में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 334 क्षेत्रांतर्गत सफाई का कार्य कराया गया। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिद्वार दीपक वर्मा ने अवगत कराया है कि सिडकुल क्षेत्रांतर्गत फोर लाइन सड़क किनारे साफ सफाई कराई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने अवगत कराया है की एकम्स कंपनी के माली के सहयोग से आपदा की टीम द्वारा कार्यालय कैंपस एवं बाहर रेलिंग में उगी झाड़ियों की कटान कर साफ सफाई कराई गई। खंड विकास अधिकारी नारसन ने अवगत कराया है कि नारसन क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोतवाल आलमपुरा, लखनौता, मखदूमपुर आदि क्षेत्रों में सड़क किनारे पड़े मिट्टी को उठाया गया इसके साथ ही साफ सफाई कराई गई। खंड विकास अधिकारी रुड़की ने अवगत कराया है कि रुड़की क्षेत्रांतर्गत सोहलपुर गढ़ा में सफाई के कार्य कराया गया। महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी ने अवगत कराया है कि रायपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नालियों की सफाई के साथ चलाया गया सफाई अभियान।

प्रशिक्षु महिला अधिवक्ता दुर्घटना में घायल, मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

रानीपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार प्रशिक्षु महिला अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला के दोनों पैरों और एक हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, जमालपुर कलां निवासी शोभा देवी बालियान जिला न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता के चैंबर में प्रशिक्षण ले रही हैं। 23 दिसंबर को वह स्कूटी से रोशनाबाद कचहरी जा रही थीं। जैसे ही वह पीएसी गेट के पास पहुंचीं, पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनके दोनों पैर और एक हाथ में फ्रैक्चर होने की पुष्टि की।

रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

अंकिता भंडारी प्रकरण में कोई वीआईपी संलिप्त नहीं, तीनों अभियुक्तों को सजा

उत्तराखण्ड पुलिस ने तथ्यों के साथ किया बड़ा खुलासा '

पथ प्रवाह, देहरादून।

अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया एवं कुछ माध्यमों में लगातार फैल रही भ्रामक सूचनाओं, आधे-अधूरे तथ्यों और निराधार आरोपों के बीच उत्तराखण्ड पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की। पुलिस ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में किसी भी प्रकार का कोई वीआईपी एंगल नहीं है और इस तथ्य को माननीय न्यायालय भी स्वीकार कर चुका है।

उत्तराखण्ड पुलिस ने बताया कि वायरल ऑडियो और कथित बातचीत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा निष्पक्ष, विस्तृत एवं गहन विवेचना की गई, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। एसआईटी टीम का हिस्सा रहे शेखर सुयाल ने मीडिया को बताया कि इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य न तो नष्ट किया गया और न ही छिपाया गया। जिस कमरे को लेकर बार-बार यह आरोप लगाया गया कि उसे साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तोड़ा गया, उसकी वीडियोग्राफी सहित सभी आवश्यक साक्ष्य विधिवत रूप से तीनों न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान ही कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो वर्तमान में भी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस ने बताया कि तथाकथित वीआईपी एंगल सामने आने के बाद रिसोर्ट में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की गई। एसआईटी ने रिसोर्ट के सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अंकिता पर 'एक्स्ट्रा सर्विस' देने का दबाव बनाया गया था। अंकिता द्वारा इनकार करने पर ही आरोपियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कर्मचारियों के बयानों से यह भी स्पष्ट हुआ कि अंकिता मानसिक रूप से परेशान थी और वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आरोपियों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाया।

पुलिस रिमांड के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर ही शव की बरामदगी की गई, जो पूरी तरह विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत हुई। इसके अतिरिक्त अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा फेसबुक लाइव एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लगाए गए आरोपों को लेकर अलग से एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उर्मिला सनावर को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसका अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पुलिस ने बताया कि उर्मिला सनावर द्वारा सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन उनके पत्र में कोई स्पष्ट पता नहीं है। जांच में सहयोग करने पर उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं है। मार्च 2025 के एक पुराने प्रकरण में उनके खिलाफ जारी सम्मन का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

उत्तराखण्ड पुलिस ने मीडिया और आम जनता से अपील की कि यदि किसी के पास इस प्रकरण से जुड़ी कोई भी अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य हों तो वे सामने आकर पुलिस को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने पुनः दोहराया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच पूरी तरह निष्पक्ष, तथ्यपरक और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है तथा किसी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

जनता की समस्याओं का समय से करें निस्तारण, योजनाओं का पात्रों को दें लाभः पीआर चौहान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीआर चौहान की अध्यक्षता में विकासखंड रुड़की की न्याय पंचायत खाताखेडी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाताखेड़ी प्रथम में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनों से 304 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 513 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। इस शिविर में 2431 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग ?।

आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 86 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें 46 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया,शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण

समिति देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना है तथा उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित करना है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीआर चौहान ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। इस अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। शिविर में झबरेडा विधायक वीरेंद्र जाति, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अनीश गौड़, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा नीलकमल शर्मा, खंड विकास अधिकारी सुमन कोटियाल सहित क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी व कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

विकास खण्ड खानपुर में शिविर

उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल की अध्यक्षता में विकास खंड खानपुर के न्याय पंचायत गोरधनपुर के जूनियर हाई स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। शिविर में 232 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 279 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 2104 लोगों ने प्रतिभाग किया। शिविर में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 33 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए। उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवसियो की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर में ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी एवं भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

एक नजर

दिल्ली में शनिवार को 72 उड़ानें रद्द, 300 से ज्यादा में देरी

नयी दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को खराब मौसम के कारण 72 उड़ानें रद्द रहीं और 300 से अधिक की उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई।

दिल्ली में आज सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे के कारण वहां से आने वाली और वहां जाने वाली उड़ानें रद्द रहीं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विमान सेवा कंपनियों ने आज दिल्ली आने वाली 34 और यहां से जाने वाली 38 उड़ानें रद्द कीं। इसके अलावा 300 से अधिक उड़ानों में देरी की भी सूचना है। उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली में रनवे पर दृश्यता ठीक रही, लेकिन दूसरे शहरों में कोहरा रहा। विमान सेवा कंपनियों ने धर्मशाला, भुवनेश्वर, इंदौर, दरभंगा और हैदराबाद में कोहरा होने की सूचना देते हुए यात्रियों को अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की सलाह दी है।

महीनों बर्फ में गुम रहे रोबोट ने लाई ऐसी जानकारी कि वैज्ञानिक भी दंग

लंदन। करीब 9 महीनों तक अंटार्कटिका के ग्लेशियर में गुम रहा एक छोटा रोबोट जब वापस लौटा तो ऐसी जानकारी लेकर आया कि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। वैज्ञानिकों ने इसे टॉटन ग्लेशियर के पास छोड़ा था। वहां की बर्फ पूरी तरह पिघले तो समुद्र का जलस्तर 3.5 मीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन यह रोबोट जल्दी ही बहकर दूर चला गया। इस रोबोट को आर्गो फ्लोट कहते हैं, जो समुद्र में तापमान और नमक की मात्रा नापता है। वैज्ञानिक निराश हो गए, क्योंकि वे टॉटन की बर्फ पिघलने की वजह जानना चाहते थे। अब यह रोबोट डेनमन और शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे से गुजरकर लौटा। रोबोट ने नौ महीने बर्फ के नीचे बिताए और बहुत जरूरी जानकारी इकट्ठा की। जानकारी के अनुसार, आर्गो फ्लोट एक ऑटोमेटिक रोबोट है जो समुद्र में घूमता है। यह दो किलोमीटर गहराई तक जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हर दस दिन में सतह पर आकर डेटा सैटेलाइट से भेजता है। दुनिया भर में ऐसे हजारों फ्लोट काम करते हैं। इस रोबोट ने पहली बार पूर्वी अंटार्कटिका की आइस शेल्फ के नीचे हर पांच दिन में तापमान का डेटा लिया। अंटार्कटिका की आइस शेल्फ तैरती हुई बड़ी बर्फ की चादरें हैं। ये जमीन की बर्फ को समुद्र में जाने से रोकती हैं। अगर नीचे से गर्म पानी आए तो ये पिघल जाती हैं। पिघलने पर जमीन की बर्फ तेजी से समुद्र में गिरती है और जलस्तर बढ़ता है। डेनमन ग्लेशियर में इतनी बर्फ है कि पूरी पिघले तो जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ जाए। शैकलटन आइस शेल्फ पूर्वी अंटार्कटिका की सबसे उत्तरी शेल्फ है। वैज्ञानिकों जानना चाहते थे कि गर्म पानी इनके नीचे पहुंच रहा है या नहीं। यह काम अब रोबोट ने कर दिया। रोबोट टॉटन से बहकर डेनमन के पास पहुंचा। वहां गर्म पानी बर्फ के नीचे जा रहा था, जो पिघलने का कारण बन सकता है। फिर रोबोट बर्फ के नीचे चला गया। वैज्ञानिकों को लगा कि अब यह कभी नहीं लौटेगा। लेकिन नौ महीने बाद यह डेनमन और शैकलटन के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। इस दौरान इसने 300 किलोमीटर का सफर तय किया और करीब 200 बार डेटा लिया। बर्फ के नीचे होने से जीपीएस नहीं मिलता था, लेकिन रोबोट जब बर्फ से टकराता तो मोटाई नाप लेता। सैटेलाइट की पुरानी जानकारी से मिलाकर वैज्ञानिकों ने इसका रास्ता पता कर लिया। डेटा से पता चला कि शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे अभी गर्म पानी नहीं पहुंच रहा। वहां पानी ठंडा है और बर्फ फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन डेनमन के नीचे गर्म पानी जा रहा है, जो बर्फ पिघला रहा है।

फर्जी यूपीएससी रिजल्ट के नाम पर युवक से ठगी, एलबीएस मसूरी पहुंचा पीड़ित

पथ प्रवाह, देहरादून/मसूरी।

एल.बी.एस. प्रशासन, मसूरी द्वारा दी गई सूचना के बाद कोतवाली मसूरी पुलिस ने फर्जी यूपीएससी रिजल्ट के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंचे एक युवक के मामले का खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक स्वयं किसी षड्यंत्रकर्ता का नहीं बल्कि एक संगठित ठगी का शिकार हुआ है।

जानकारी के अनुसार, 03 जनवरी 2026 को एल.बी.एस. प्रशासन मसूरी ने कोतवाली मसूरी को सूचित किया कि एक युवक फर्जी यूपीएससी परिणाम के आधार पर प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लेने के उद्देश्य से संस्थान परिसर में उपस्थित हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली मसूरी से वरिष्ठ उप निरीक्षक तत्काल पुलिस बल के साथ एल.बी.एस. परिसर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एलआईयू (LIU) मसूरी एवं आईबी (IB) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

मौके पर युवक से पूछताछ की गई तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि युवक द्वारा प्रस्तुत किया गया यूपीएससी रिजल्ट फर्जी है तथा युवक स्वयं इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। युवक फर्जी चयन पत्र के आधार पर अपने माता-पिता एवं दैनिक उपयोग का सामान लेकर एलबीएस मसूरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पहुंचा था। इसके पश्चात युवक को आवश्यक पूछताछ हेतु कोतवाली मसूरी लाया गया। थाने पर की गई विस्तृत पूछताछ में पता चला कि युवक उच्च शिक्षित है और वर्तमान में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। पूछताछ के दौरान युवक ने इस संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र भी पुलिस को सौंपा। जांच में यह भी सामने आया कि Pushpesh Singh पुत्र राकेश कुमार सिंह, निवासी-अरियॉव पोस्ट फुलवरिया ताजपुर, थाना दाउतपुर, जिला सारण (बिहार), वर्तमान पता–प्लॉट नंबर 601, सेक्टर-21, मुल्ला हेरा, पॉकेट-सी (ई), सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) द्वारा यूपीएससी परीक्षा में चयन दिलाने के नाम पर युवक से कुल 27,564 रुपये की धनराशि ठगी गई। इसमें 13,000 रुपये नकद तथा 14,564 रुपये यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से युवक को फर्जी यूपीएससी रिजल्ट भेजा गया।

चूंकि उक्त आपराधिक प्रकरण का संबंध गुरुग्राम, हरियाणा से पाया गया है, इसलिए कोतवाली मसूरी में मु0अ0सं0- (जीरो) 00/2026, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए यह प्रकरण संबंधित राज्य को प्रेषित किया जाएगा।

आखिरकार क्यों हैं पाकिस्तानी की सबसे ताकतवार कंपनी फौजी फाउंडेशन

कराची। पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालिया घटनाक्रम में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीएआई) के निजीकरण और फौजी फाउंडेशन में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की संभावित हिस्सेदारी ने सवाल खड़ा किया है कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कंपनी फौजी फाउंडेशन आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक दबाव में यूएई को फौजी फाउंडेशन में करीब एक अरब डॉलर की हिस्सेदारी देने की अनुमति दे दी। इसके बदले अबू धाबी से दो अरब डॉलर के कर्ज के रोलओवर की उम्मीद जाहिर की है। इससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान की सेना से जुड़ी कारोबारी संस्थाएं अब केवल घरेलू नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सौदों का भी अहम हिस्सा बन चुकी हैं। फौजी फाउंडेशन को अक्सर पाकिस्तान सेना की 'मनी मशीन' कहा जाता है। इसकी मौजूदगी करीब हर मुनाफे वाले सेक्टर में है। खाद और सीमेंट निर्माण से लेकर बिजली उत्पादन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट निवेश और इतना ही नहीं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक–हर जगह फौजी फाउंडेशन का दखल है। यह पाकिस्तान के उस मिलिट्री-कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्स का केंद्र है, जिसके जरिए सेना केवल रक्षा ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है। फौजी फाउंडेशन अकेला नहीं है। यह पाकिस्तानी नौसेना के बहरिया फाउंडेशन और वायुसेना के शाहीन फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करता है। इन संस्थाओं के भी अपने-अपने बिजनेस हैं, जो शिपिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट (एडब्ल्यूटी) है, जो दो दर्जन से ज्यादा व्यावसायिक कंपनियों को नियंत्रित करता है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) भी सेना से जुड़ी एक शक्तिशाली रियल एस्टेट संस्था है, जिसने पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर में कीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है। फौजी फाउंडेशन की स्थापना 1952 में हुई थी। शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन से केवल 3.6 मिलियन डॉलर की पूंजी मिली थी, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण था। लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। आज, 2025 तक, इसके तहत कम से कम 25 सूचीबद्ध कंपनियां और कई गैर-सूचीबद्ध संस्थाएं काम कर रही हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार, फौजी फाउंडेशन की कुल नेटवर्थ लगभग 5.9 अरब डॉलर है, जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कॉरपोरेट समूह बनाती है।

सोशल मीडिया शिकायत पर डीएम सख्त, बेस अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

सोशल मीडिया पर सामने आई एक शिकायत को जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जिला स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। केली उत्तराखंड (चद्द्द्य4 ह्लह्लड्डह्स्ड्डम्द्धड्डठ्ठस्त्र) नामक फेसबुक पेज पर प्रसारित एक वीडियो में बेस अस्पताल अल्मोड़ा में अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध न होने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने बेस अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां संबंधित स्टाफ उपलब्ध नहीं था, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल और बेस अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में किसी भी आपातकालीन या तात्कालिक स्थिति में मरीजों को इस प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सी.पी. भैंसोड़ा से जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित दिनांक को अल्ट्रासाउंड करने वाले रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर थे, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों अस्पताल आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और मरीज को तत्काल आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी एक अस्पताल में किसी कारणवश कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो जिला अस्पताल और बेस अस्पताल को एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल में तुरंत सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों अस्पताल एक-दूसरे के निकट स्थित हैं, इसलिए इसे रेफरल कहना उचित नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अल्मोड़ा मुख्यालय में संचालित दोनों बड़े अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी अस्पताल में अस्थायी रूप से सुविधा उपलब्ध न हो, तो दूसरे अस्पताल में जाकर उपचार कराया जा सकता है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जनता को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

राजस्व वसूली से लेकर आपदा मुआवजे तक डीएम ने कसी प्रशासनिक कसावट

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित स्टाफ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद की राजस्व वसूली, लंबित वादों के निस्तारण, किसान योजनाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विभिन्न लंबित राजस्व एवं अन्य वादों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर वादों का निस्तारण न केवल आमजन को त्वरित न्याय दिलाता है, बल्कि प्रशासन की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के सत्यापन और पंजीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाने और अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बीते समय में घटित आपदाओं से प्रभावित लोगों को नियमानुसार शत-प्रतिशत मुआवजा वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन का गहन अध्ययन करने, प्रभावित जनोपयोगी परिसंपत्तियों का नियमानुसार आगणन तैयार करने तथा दुर्घटनाओं के पश्चात होने वाली मजिस्ट्रियल जांचों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पारदर्शी, संवेदनशील और निष्पक्ष प्रशासनिक प्रणाली सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसके लिए प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करना होगा। अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, द्वाराहाट सुनील कुमार राज सहित अन्य उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, आईएमडी ने येलो अलर्ट किया जारी

नयी दिल्ली। राजधानी में शनिवार सुबह हवा की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सुबह के समय घने कोहरे के कारण 'येलो अलर्ट' जारी किया। इस कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित रही।

सुबह करीब आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 235 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 248, रोहिणी में 270, आईटीओ में 219, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में 148 दर्ज किया गया।

कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप तेज, कई स्थानों पर शून्य से काफी नीचे तापमान दर्ज

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर शून्य से नीचे तापमान पहुंच जाने के साथ ही ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात दर्ज किये गये तापमान से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। घाटी के पर्यटन स्थलों में ठंड का प्रकोप और ज्यादा रहा, स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, हालांकि पिछली रात की तुलना (शून्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे) में यह थोड़ा अधिक था। पहाड़ी रिसॉर्ट पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यहां तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा गिरकर शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया, जो पिछली रात के 0.8 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले काफी कम है। दक्षिण कश्मीर के जिलों में भी रातें काफी सर्द रहीं। शोपियां में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 3.8 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले काफी गिरावट को दिखाता है। पुलवामा में तापमान पिछली रात के शून्य से 2.4 डिग्री के मुकाबले तापमान गिरकर 3.9 शून्य से डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर संभाग के कई हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से शून्य से तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, जबकि जम्मू संभाग के कई इलाकों में तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर तक दर्ज किया गया। भद्रवाह जम्मू संभाग का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर में मुख्य रूप से शुष्क मौसम का अनुमान जताया है।

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान आठ जनवरी से होगा शुरू

नयी दिल्ली। कांग्रेस पार्टी आगामी आठ जनवरी से देशभर में 'मनरेगा बचाओ' अभियान शुरू करेगी। यह राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन 45 दिनों तक चलेगा और इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने यहां पार्टी मुख्यालय में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान करते हुए कहा कि मनरेगा की जगह लाया गया नया अधिनियम श्रमिकों के हकों को छीनता है। यह नया कानून अधिकार आधारित रोजगार पर प्रहार करता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा की जगह नया कानून लाकर सरकार का मकसद रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना को खत्म करना है इसलिए कांग्रेस कार्यसमिति ने पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ' अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए श्री वेणुगोपाल ने कहा कि आठ जनवरी से सभी राज्यों में बड़ी बैठकें की जायेंगी, जिनमें प्रदेश के सारे बड़े नेता और प्रभारी मौजूद रहेंगे। इन बैठकों में सभी जिलों को कुछ दायित्व दिए जायेंगे। इसके बाद 10 जनवरी को सभी जिलों में संवाददाता सम्मेलन करके पंचायती राज को खत्म करने की साजिश को उजागर किया जाएगा। सभी जिलों में 11 जनवरी को महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने एक दिन का उपवास किया जाएगा और 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हर पंचायत में चौपाल लगाई जायेगी।

श्री वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा जाएगा। वार्ड और ब्लॉक स्तर पर 30 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। विधानसभा और राजभवन का घेराव कार्यक्रम 7 से 15 फरवरी के बीच किया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच बड़ी रैलियां भी करेगी।

उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार की अहम व्यवस्था बताते हुए कहा है कि इसकी जगह लाया गया वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के साथ धोखा है इसलिए सरकार को तत्काल मनरेगा को उसके मूलरूप में बहाल करना चाहिए।

श्री वेणुगोपाल ने कहा कि मनरेगा देश की सबसे बेहतरीन मांग आधारित गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से एक है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस योजना को खूब प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने कहा कि हर साल, 5-6 करोड़ ग्रामीण परिवार मनरेगा के तहत अपने गांवों में काम करते हैं। संकट के समय में, यह योजना गरीबों के लिए सबसे मजबूत सहारा बन जाती है लेकिन वीबी-जी रामजी के तहत रोजगार अब अधिकार नहीं रह गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके तहत काम केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पंचायतों में ही उपलब्ध कराया जाएगा और यदि किसी पंचायत का चयन नहीं होता है, तो वहां लोगों को गरीबी या संकट की स्थिति में भी काम का अधिकार नहीं होगा। उनका कहना था कि यह सरकार की चुपचाप काम के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश है क्योंकि इससे कम वेतन और वेतन में कटौती का रास्ता खुल जाता है, जिससे श्रमिक और भी गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।

उन्होंने योजना के नाम से महात्मा गांधी के नाम हटाने को अत्यंत निंदनीय कृत्य करार दिया और कहा कि महात्मा गांधी महज एक प्रतीक नहीं हैं। उनका नाम हटाना मनरेगा में निहित अधिकार आधारित उनके दृष्टिकोण को मिटाने का प्रयास है।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com